



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 33-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 13, 2024 (SRAVANA 22, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2024

संख्या 2/14/2018-1पेंशन (एफ डी).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) तथा हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-II नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2016 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

इन नियमों का लागूकरण।

2. (1) ये हरियाणा सरकार के उन सभी न्यायिक अधिकारियों पर लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं/उनकी मृत्यु हो गई है और जो पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से विकलनीय है।

(2) ये नियम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

प्रभाव की तिथि।

3. इन नियमों के अनुसार पुनरीक्षित उपबंध, उन न्यायिक अधिकारियों को लागू होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है:

परन्तु जहाँ पेंशन/पारिवारिक पेंशन या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन का सरांशीकरण, प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद आने वाले मामले में पहले ही स्वीकृत हो चुका है, उसे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उन मामलों में जहाँ पेंशन पूर्व-पुनरीक्षित परिलाभों पर अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है और यदि यह इन नियमों के अधीन हकदारी पेंशन से अधिक लाभकारी है, तो पहले से स्वीकृत पेंशन, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 78 के परंतुक को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगियों के अलाभ के लिए पुनरीक्षित नहीं की जाएगी।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए परिलाभ।

4. मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान से अन्यथा विभिन्न पेंशनरी लाभों को संगणित करने के प्रयोजनों के लिए "परिलाभों" का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 9 के उप-नियम (7) के खण्ड (ख) में यथा विहित है।

5. पुनरीक्षित वेतन ढांचा में वेतन से अभिप्राय है, प्रथम जनवरी, 2016 से वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में प्राप्त किया गया वेतन किन्तु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे कि विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है। मूल वेतन।
6. सेवानिवृत्ति/मुत्तु की तिथि को अनुज्ञेय सभी प्रकार के उपदान, मंहगाई भत्ते, इन नियमों के नियम 4 के अनुसार यथा परिभाषित परिलाभों सहित परिलाभों के रूप में समझे जाएंगे। मुत्तु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलाभ।
7. दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पूर्व पंजाब सिविल सेवा नियम, वाल्यूम II [अब हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016] के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला न्यायिक अधिकारी, पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा, किन्तु वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 32 तथा 35 के अनुसार सेवा उपदान के लिए हकदार समझा जाएगा। पेंशन।
8. (1) कोई न्यायिक अधिकारी, जो बीस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो वह हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के उपबंधों के अधीन पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। पेंशन की संगणना हेतु उपबंध।
- (2) सभी ऐसे मामलों में, जहाँ कोई न्यायिक अधिकारी, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के अनुसार दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद अधिवर्षिता पर पेंशन का हकदार हो गया है, तो उसकी पेंशन, उसे अनुज्ञेय पूर्ण पेंशन की राशि के अनुपातिक आधार पर संगणित की जाएगी।
9. (1) हरियाणा सरकार में प्रथम जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि, क्रमशः प्रतिमास पेंशन 38,920/- रुपए और पारिवारिक पेंशन 23,350/- रुपए और उच्चतर वेतन प्रतिमास 2,24,100/- रुपए का पचास प्रतिशत अर्थात् अधिकतम पेंशन प्रतिमास 1,12,050/- रुपए और तीस प्रतिशत अर्थात् अधिकतम पारिवारिक पेंशन प्रतिमास 67,230/- रुपए के अध्वधीन होगी। पेंशन और पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम सीमा।
- (2) उप-नियम (1) के उपबंध, उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहाँ किसी न्यायिक अधिकारी का सेवाकाल उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर बीस वर्ष से कम है। इन न्यायिक अधिकारियों की पेंशन, उनके सेवाकाल के दृष्टिगत हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 में विहित उपबंधों के अनुसार आनुपातिक रूप से संगणित की जाएगी।
10. (1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में यथा वर्णित के अनुसार संगणित की जाएगी, अर्थात्:- अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन।

तालिका

क्रम संख्या	पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा निम्नलिखित आयु प्राप्त करने पर	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
1	2	3
1.	75 वर्ष किन्तु 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
2.	80 वर्ष किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
3.	85 वर्ष किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
4.	90 वर्ष किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60 प्रतिशत
5.	95 वर्ष किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80 प्रतिशत
6.	100 वर्ष या से अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(2) प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की जन्म तिथि और आयु पेन-I तथा पेंशन भुगतान आदेश में निरपवाद रूप से दर्शाई गई है ताकि पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ज्योंहि देय होती है, के भुगतान को सुकर बनाया जा सके। यदि आवश्यक सूचना, पेन-1 [प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा द्वारा जारी] में उपलब्ध नहीं है, तो उन मामलों में, अतिरिक्त पेंशन को विद्यमान मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में जोड़ने से पूर्व प्रधान महालेखाकार (लेखा तथा हकदारी), हरियाणा से आवश्यक सूचना प्राप्त की जाएगी। अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि को पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा।

उदाहरण: यदि जहाँ पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी 75 वर्ष से अधिक आयु का है तथा उसकी समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन इन नियमों के नियम 8 के अनुसार 10,000/— रूपए प्रतिमास है, तो पेंशन/पारिवारिक पेंशन (i) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन 10,000/—रूपए तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन = 2000/— रूपए प्रतिमास अनुसार दर्शाई जाएगी।

(3) 75 वर्ष तथा से अधिक की आयु पूरी करने पर, पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि, मास के प्रथम दिन से अनुज्ञेय होगी, जिसमें उसके जन्म की तिथि पड़ती है।

उदाहरण:— यदि कोई पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी मई, 2023 में किसी भी तिथि को 75 वर्ष की आयु पूरी करता है, तो वह प्रथम मई, 2023 से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर मंहगाई राहत भी, समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति
उपदान।

11. (1) मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा 20 लाख (बीस लाख) रूपए होगी। जब भी मंहगाई भत्ते में वृद्धि, मूल वेतन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक हो जाती है, तो उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) की बढ़ोतरी की जाएगी।

(2) मृत्यु उपदान की दर, नीचे दी गई तालिका में यथा वर्णित अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी, अर्थात्:—

तालिका

क्रम संख्या	मृत्यु की अर्हक सेवाकाल की अवधि	मृत्यु उपदान की दर
1	2	3
1	1 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का दो गुणा
2	एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 6 गुणा
3	5 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 12 गुणा
4	11 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलाभों का 20 गुणा
5	20 वर्ष या उससे अधिक	मासिक परिलाभों का अधिकतम 33 गुणा के अध्यधीन अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह मास की अवधि के लिए अर्ध मास के परिलाभ।

पारिवारिक पेंशन
स्कीम, 1964।

12. (1) पारिवारिक पेंशन, पुनरीक्षित वेतन ढांचे में मूल वेतन के 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) की एकरूप दर पर संगणित की जाएगी तथा हरियाणा सरकार में प्रथम जनवरी, 2016 से न्यूनतम 23,350/— रूपए प्रतिमास तथा अधिकतम 67,230/—रूपए प्रतिमास अर्थात् उच्चतर वेतन 2,24,100/— रूपए का 30 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(2) वर्धित पारिवारिक पेंशन की राशि, हरियाणा सरकार में पुनरीक्षित वेतन ढांचे में मूल वेतन का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) होगी और न्यूनतम 38,920/—रूपए प्रतिमास और अधिकतम उच्चतर वेतन का 50 प्रतिशत के अध्यधीन होगी।

(3) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए आश्रित परिवार के सदस्य (पति या पत्नी से भिन्न) की आय सीमा, प्रतिमास 30,000/— रूपए (केवल तीस हजार) से कम होनी चाहिए।

पारिवारिक पेंशन।

13. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "पारिवारिक पेंशन" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (10) के उप-खण्ड (ख) में यथा परिभाषित पारिवारिक पेंशन।

पेंशन का
संराशिकरण।

14. संराशिकरण मूल्य, सीमा, जिस तक पेंशन संराशित की जा सकती है अथवा अवधि, जिसके बाद संराशित पेंशन बहाल की जानी है, से संबंधित उपबंधों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

मंहगाई राहत की
स्वीकार्यता।

15. इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्रथम जनवरी, 2016 से "मूल पेंशन" या "मूल पारिवारिक पेंशन" जैसी भी स्थिति हो, समझा जाएगा। उसके बाद, प्रथम जनवरी, 2016 से मंहगाई राहत सहित प्राप्त की गई पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, स्वीकृत मंहगाई राहत प्रदान करने के लिए अर्हक होगी।

16. न्यायिक अधिकारियों, जो प्रथम जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं/या उनकी मृत्यु हुई है और उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 2/14/2018-1Pension (FD), दिनांक 12 जून, 2019 के अनुसार मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 30 प्रतिशत की दर पर पहले ही भुगतान की जा चुकी अंतरिम राहत के समायोजन के बाद, पेंशन संवितरण प्राधिकारी प्रथम जनवरी, 2016 से भुगतानयोग्य पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों की गणना करेगा और बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करेगा।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का भुगतान।

17. (1) यह सम्भाव्य है कि कुछ मामलों में देय बकायों का अधिक भुगतान गलती से संगणित किया जा सकता है, जो कार्यान्वयन के बाद भी बाद में वसूल किया जाना है। इसलिए पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को बकायों को आहरण करते समय हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों से यह स्पष्ट करवा लेना चाहिए कि यदि बाद में कोई विसंगति ध्यान में आती है, तो भुगतान, उन राशियों से समायोजन के अध्यक्षीन किया जा रहा है, जो उनको देय होगी। इस प्रयोजन के लिए, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के समय पर प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों से लिखित में इस आशय की वचनबद्धता भी प्राप्त की जाएगी कि अधिक भुगतान, जो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत समेकन के परिणामस्वरूप किया गया पाया जा सकता है, तो, उस द्वारा सरकार को या तो भविष्य में भुगतान के समायोजन द्वारा या अन्यथा से उक्त राशि वापस की जाएगी। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के अधिक भुगतान की वसूली के लिए वचनबद्धता।

(2) पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नियतन तथा बकायों का समायोजन भी उन कतिपय मामलों में परिशोधन तथा समायोजन के अध्यक्षीन होगा, जहाँ विशेष पेंशन या अनन्तिम पेंशन विधि न्यायालय के कुछ अंतरिम आदेशों की सामर्थ्य में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को प्रदान की गई थी, मामले के अंतिम रूप से निर्णित होने के बाद, विधि न्यायालय की टिप्पणी/निर्देश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए, पेंशन संवितरण प्राधिकारी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकायों का वितरण करते समय हरियाणा सरकार के ऐसे सभी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके पात्र पारिवारिक सदस्यों को यह भी स्पष्ट करेंगे कि विधि न्यायालय के ऐसे अन्तिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए समुचित निर्णय के अध्यक्षीन भुगतान किए जा रहे हैं। वचनबद्धता का नमूना प्ररूप अनुलग्नक 'ख' में दिया गया है।

18. इन नियमों या इन नियमों की निरन्तरता में जारी किए गए किन्हीं अन्य पश्चात्तर्वर्ती अनुदेशों में यथा उपबन्धित के सिवाय, हरियाणा सिविल सेवा नियम या पंजाब वित्त नियम या इस संबंध में बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या जारी किए गए अनुदेशों के उपबन्ध, ऐसे मामलों, जहाँ पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाता है, को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक वे इन नियमों से असंगत हों। पंजाब सिविल सेवा नियम वाल्यूम II तथा अन्य नियमों, जो इन नियमों द्वारा विशेष रूप से उपांतरित नहीं किए गए हैं, के उपबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे।

अध्यारोही प्रभाव।

19. यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो अन्तिम निर्णय के लिए इसे वित्त विभाग में हरियाणा सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

निर्वचन।

20. किसी सामान्य या विशेष परिस्थितियों की स्थिति में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं या जिनके बारे में कतिपय असंगति ध्यान में आई हों, तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार ऐसी परिस्थितियों के अधीन अनुपालित की जाने वाली शर्तें विहित करेगी। इन नियमों के अधीन सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी। आगे, यदि सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कतिपय अतिरिक्त शर्तों को विहित करने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी शर्तें विहित कर सकती है और हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित ऐसी अतिरिक्त शर्तें इन नियमों का भाग रूप समझी जाएंगी।

अवशिष्ट उपबन्ध।

21. जहाँ सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो यह आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों, के अध्यक्षीन इन नियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकती है या में ढील दे सकती है, जो यह मामले को न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति में निपटाने के लिए आवश्यक समझे।

ढील देने की शक्ति।

22. पेंशन संवितरण प्राधिकारी/खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लाभ के लिए इन नियमों को अपने सूचनापट्ट पर तत्काल प्रदर्शित करेंगे।

प्रदर्शन।

अनुलग्नक क

[देखिए नियम 17(1)]

वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि यदि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के गलत नियतन के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है या बाद में ध्यान में आई विसंगतियों के दृष्टिगत कोई अधिक भुगतान किया गया पाया जाता है, तो मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

अनुलग्नक ख
[देखिए नियम 17(2)]
वचनबद्धता

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ/देती हूँ कि किसी विधि न्यायालय के किसी अंतरिम आदेश के आधार पर मुझे दी गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन में किसी परिशोधन या समायोजन के परिणामस्वरूप कोई अधिक राशि, जो विधि न्यायालय के अंतिम निर्णय पर सरकार द्वारा लिए गए सुसंगत समुचित निर्णय के परिणामस्वरूप का भुगतान किया गया पाया जाता है, तो वह मेरे द्वारा सरकार को या तो मुझे देय आगामी भुगतानों के समायोजन द्वारा या अन्यथा से वापस किया जाएगा। मैं, आगे ऐसे विधि न्यायालय के यथास्थिति अंतिम निर्णय पर लिए गए सरकार के ऐसे सुसंगत समुचित निर्णय का पालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**FINANCE DEPARTMENT****Notification**

The 5th August, 2024

No. 2/14/2018-1Pension(FD).— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

Short title and commencement.	<p>1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Service (Judicial Branch) and the Haryana Superior Judicial Service (Revised Pension) Part - II Rules, 2024.</p> <p>(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.</p>
Applicability of these rules.	<p>2. (1) They shall apply to all Judicial Officers of the Haryana Government, who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016 and who become eligible for pension /family pension under the Punjab Civil Services Rules, Volume II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016), whose pension /family pension is debitable to the Consolidated Fund of the State of Haryana.</p> <p>(2) These rules shall not apply to Judges of the Punjab and Haryana High Court.</p>
Date of effect.	<p>3. The revised provision as per these rules shall apply to Judicial Officers, who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016:</p> <p>Provided that where pension/family pension or death-cum-retirement gratuity/commutation of pension, has already been sanctioned in cases occurring on or after the 1st January, 2016, the same be revised as per provision of these rules:</p> <p>Provided further that in cases where pension has been finally sanctioned on pre revised emoluments and if the same happens to be more beneficial than the entitled pension under these rules, the pension already sanctioned shall not be revised to the disadvantage of the pensioner in view of proviso to rule 78 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.</p>
Emoluments for pension / family pension.	<p>4. The term “emoluments” for the purposes of calculating various pensionary benefits other than death cum retirement gratuity shall mean pay as defined in clause (b) of sub-rule (7) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.</p>
Basic pay.	<p>5. Basic pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the Pay Matrix with effect from the 1st January, 2016 but does not include any type of pay like special pay etc.</p>
Emoluments for death-cum-retirement gratuity.	<p>6. In the case of all kinds of gratuity, dearness allowance admissible on the date of retirement/death shall continue to be treated as emoluments along with the emolument as defined in terms of rule 4 of these rules.</p>
Pension.	<p>7. A Judicial Officer retiring in accordance with the Punjab Civil Services Rules Vol. II (now the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016) before completing qualifying service of ten years shall not be entitled to pension but he shall continue to be entitled to service gratuity in terms of rules 32 and 35 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.</p>
Provision for calculation of pension.	<p>8. (1) A Judicial Officer, who retires after rendering the minimum qualifying service of 20 years, shall become entitled to full pension under the provisions of rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.</p> <p>(2) In all such cases, where Judicial Officer becomes entitled to pension on superannuation after completion of 10 years of qualifying service in accordance with the rule 34 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, pension shall be calculated on proportion basis to the amount of full pension admissible to him.</p>
Minimum and maximum ceiling of pension and family pension.	<p>9. (1) The amount of pension and family pension shall be subject to a minimum of Rs. 38920/- per month and Rs. 23350/- per month respectively and the maximum Rs. 1,12,050/- per month i.e. 50% (fifty percent) and family pension Rs. 67,230/-per month i.e. 30% (thirty percent) of the highest pay of Rs. 2,24,100/-per month in the Government of Haryana with effect from the 1st January, 2016.</p>

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply in those cases where the length of service of a Judicial Officer at the time of his retirement is less than 20 years. The pension of these Judicial Officers shall be calculated proportionately as per provisions specified in the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 keeping in view his length of service.

10. (1) The quantum of additional pension/family pension available to the retired *Judicial Officers and their eligible family members* shall be as mentioned in the table given below, namely:-

Additional pension/family pension.

Table

Serial Number	Attaining age of pensioner /family pensioner	Additional quantum of pension/family pension
1	2	3
1	From 75 years to less than 80 years	20% of revised basic pension/family pension
2	From 80 years to less than 85 years	30% of revised basic pension/family pension
3	From 85 years to less than 90 years	40% of revised basic pension/family pension
4	From 90 years to less than 95 years	60% of revised basic pension/family pension
5	From 95 years to less than 100 years	80% of revised basic pension/family pension
6	100 years or more	100 % of revised basic pension/family pension

(2) The Principal Accountant General (Accounts and Entitlement) Haryana shall ensure that the date of birth and the age of the pensioners/family pensioners is invariably indicated in PEN-I and the Pension Payment Order (PPO) to facilitate payment of additional pension/ family pension by Pension Disbursing Authority as soon as it becomes due. If the requisite information is not available in the PEN-I (issued by the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana) in those cases, the requisite information may be obtained from the Principal Accountant General (Accounts and Entitlement), Haryana before adding the additional pension/family pension in the existing basic pension / family pension. The amount of additional pension family pension shall be shown distinctly in the pension/family pension payment order.

Illustration: In case where a pensioner/family pensioner is more than 75 years of age and his/her consolidated pension/family pension in terms of rule 8 of these Rules is, Rs. 10,000/-per month, the pension/family pension shall be shown as (i) basic pension/ family pension Rs. 10,000/-and (ii) additional pension/ family pension Rs. 2,000/- per month.

(3) The additional quantum of pension/family pension on attaining the age of 75 years and above shall be admissible from the first day of the month in which his date of birth falls.

Illustration: If a pensioner / family pensioner completes age of 75 years on any date in the month of May, 2023, he shall be entitled to additional pension/family pension with effect from the 1st May, 2023.

(4) Dearness relief shall also be admissible on the additional quantum of pension/family pension available in accordance with the orders issued from time to time.

11. (1) The maximum limit of death-cum-retirement gratuity shall be Rs. 20.00 Lakh (Rs. Twenty Lakh). The ceiling on gratuity shall increase by 25% (twenty five percent) whenever the dearness allowance rises by 50% (fifty percent) of the basic pay.

Death-cum-retirement gratuity.

(2) The rate of death gratuity is revised as under:-

Table

Serial number	Length of qualifying service upto the date of death	Rate of death gratuity
1	2	3
1	Less than 1 year	2 times of monthly emoluments
2	1 year or more but less than 5 years	6 times of monthly emoluments.
3	5 year or more but less than 11 years	12 times of monthly emoluments.
4	11 year or more but less than 20 years	20 times of monthly emoluments.
5	20 years or more	half month of emolument for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emolument.

Family Pension Scheme, 1964.

12. (1) Family Pension shall be calculated at a uniform rate of 30% (thirty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs. 23,350/- per month and maximum of Rs. 67,230/- per month *i.e.* 30% (thirty percent) of the highest pay of Rs. 2,24,100/- in Government of Haryana with effect from the 1st January, 2016.

(2) The amount of enhanced family pension shall be 50% (fifty percent) of basic pay in the revised pay structure and shall be subject to a minimum of Rs. 38,920/- per month and maximum of 50% of the highest pay in the Government of Haryana.

(3) Income limit of dependent family member (other than spouse) to get family pension should be less than Rs. 30,000/- (Thirty Thousand only) per month.

Family pension.

13. For the purpose of these rules, "family pension" means, the family pension as defined in sub-clause (b) of clause (10) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016.

Commutation of pension.

14. There shall be no change in the provisions relating to commutation values, the limit upto which the pension may be commuted or the period after which the commuted pension is to be restored.

Admissibility of dearness relief.

15. The consolidated pension / family pension as worked out in accordance with the provisions of these rules shall be treated as "Basic Pension" or "Basic Family Pension", as the case may be, with effect from the 1st January, 2016. The revised pension/family pension arrived includes dearness relief from the 1st January, 2016 and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter.

Payment of arrears of pension/family pension.

16. The Pension Disbursing Authorities shall calculate the arrears of revised pension / family pension payable with effect from the 1st January, 2016 after adjustment of interim relief already paid @ 30% of the basic pension /family pension to the Judicial officers, who retire/die in harness on or after the 1st January, 2016 and their eligible family members vide Finance Department UO No. 2/14/2018-1Pension (FD), dated the 12th June, 2019 and the balance amount shall be paid immediately.

Undertaking for recovery of over payment of Pension /Family pension and gratuity.

17. (1) It is not unlikely that the arrears due in some cases may be calculated incorrectly leading to over payment that might have to be recovered subsequently. The Pension Disbursing Authorities shall, therefore, make it clear to the retired Judicial Officers and their eligible family members while drawing arrears of pension that the payments are being made subject to adjustments from amounts that may be due to them, if any, discrepancy is noticed later. For this purpose, an undertaking shall be obtained in writing from every retired Judicial Officer and his eligible family member at the time of revision of pension/family pension to the effect that excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect consolidation of pension /calculation of arrears shall be refunded by him to the Government either by adjustment against future payment or otherwise. A specimen form of undertaking is enclosed as Annexure A.

(2) The fixation of pension / family pension and adjustment of arrears shall also be subject to rectification and adjustments in certain cases where a particular pre-revised scale or provisional pension has been granted to retired Judicial Officers and their eligible family members at the strength of some interim orders of the court of law, after the final disposal of the case suitable appropriate decision may be taken by the Government keeping in view the observations / instructions of the Court of Law. The Pension Disbursing Authority shall, therefore, also make it clear to all such concerned retired Judicial Officers and their eligible family members while disbursing the arrears/ pension that payments are being made subject to appropriate decision taken by the Government on such final decision of the court of law. A specimen form of undertaking is also enclosed as Annexure B.

Overriding effect.

18. The provisions of the Haryana Civil Services Rules or the Punjab Financial Rules or any other rules or instructions made or issued in this regard shall not, save as otherwise provided in these rules or any other subsequent instructions issued in continuation to these rules, apply to cases where pension/ family pension and death-cum-retirement gratuity is regulated under these rules to the extent they are inconsistent with the provisions of these rules. The provisions of the Punjab Civil Services Rules Volume II and other rules which are not specifically modified by these rules shall remain unchanged.

- 19.** If any question arises relating to the interpretation of the provisions of these rules, it shall be referred to the Government of Haryana in Finance Department for final decision. Interpretation.
- 20.** In the event of any general or special circumstance which is not covered under these rules or about which certain inconsistencies are noticed, the matter shall be referred to the Government and the Government shall prescribe the conditions to be followed under such circumstances. Such conditions as prescribed by the Government under this rule shall be deemed to be part of these rules. Further, if the Government is satisfied that there is a requirement to prescribe certain additional conditions, the Government may prescribe such conditions and such additional conditions as prescribed by the Government of Haryana, Finance Department under this rule, shall be deemed to be the part of these rules. Residuary provisions.
- 21.** Where the Government is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order, dispense with or relax the requirements of these rules to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Power to relax.
- 22.** The Pension Disbursing Authorities/ Treasury Officers / Assistant Treasury Officers shall promptly display these rules on their notice board for the benefit of retired judicial officers. Display.

ANNEXURE A*[see rule 17 (1)]***UNDERTAKING**

I hereby undertake that in case excess payment is found to have been made as a result of incorrect fixation of pension/family pension or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Date:

Place:

Signature _____

Name _____

Address _____

ANNEXURE B
[see rule 17 (2)]
UNDERTAKING

I hereby undertake that as a result of any rectification or adjustment in the pension/family pension granted to me on the basis of any interim order by any court of law, any excess amount which is found to have been made as a result of relevant appropriate decision taken by the Government on the final decision of the court of law, shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise. I further undertake to abide by such relevant appropriate decision of the Government taken on the final decision of such court of law as the case may be.

Date:

Place:

Signature_____

Name _____

Address_____

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.